



13 August, 2024

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग प्रेमवर्क, 2024

संदर्भ: नवीनतम सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, आईआईटी मद्रास ने लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग प्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में स्वयं को शीर्ष स्थान बरकरार रखा है तथा देश की आईआईटी शीर्ष 10 में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं।

➤ समग्र शीर्ष 10 सूची -

- इस सूची में शीर्ष 10 में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- इस सूची में सात आईआईटी, आईआईएससी बेंगलुरु, एम्स दिल्ली और जेएनयू शामिल हैं।
- इस सूची में आईआईएससी बेंगलुरु ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ समग्र संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।
- जेएनयू लगातार दूसरे वर्ष 10वें स्थान पर है।

➤ विश्वविद्यालयों

- एनआईआरएफ में आईआईएससी बेंगलुरु विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष संस्थान है, यह स्थान उसने 2016 से बरकरार रखा है।
- एनआईआरएफ में दिल्ली विश्वविद्यालय 11वें स्थान से सुधरकर छठे स्थान पर पहुंचा।
- एनआईआरएफ में हैदराबाद विश्वविद्यालय 10वें स्थान से गिरकर 17वें स्थान पर आ गया।
- एनआईआरएफ में मणिपाल अकादमी, अमृता विश्व विद्यापीठम और वीआईटी शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं।

➤ इंजीनियरिंग कॉलेज

- इसमें आईआईटी मद्रास लगातार नौ वर्षों से शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है।
- अनुसंधान में आईआईटी मद्रास को दूसरा स्थान मिला है, जबकि आईआईएससी बेंगलुरु इस श्रेणी में अग्रणी है।

➤ अनुसंधान संस्थान

- एनआईआरएफ में आईआईएससी बेंगलुरु अनुसंधान संस्थानों में पहले स्थान पर है।
- एनआईआरएफ में आईआईटी मद्रास रिसर्च में दूसरे स्थान पर है।

➤ नई श्रेणियाँ

- इस वर्ष तीन नई श्रेणियाँ शुरू की गईं: मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय।

➤ भागीदारी और भविष्य की योजनाएँ

- एनआईआरएफ में 6,517 संस्थाओं द्वारा 10,845 आवेदन प्रस्तुत किये गये।
- एनआईआरएफ में मंत्रालय पड़ोसी देशों की संस्थाओं को शामिल करने तथा रैंकिंग कारक के रूप में स्थिरता को जोड़ने पर विचार कर रहा है।

➤ अतिरिक्त रैंकिंग

- इसमें आईआईएम अहमदाबाद लगातार पांचवें वर्ष शीर्ष प्रबंधन संस्थान है।
- एम्स दिल्ली लगातार सातवें वर्ष चिकित्सा विज्ञान में प्रथम स्थान पर है।
- जामिया हमदर्द फार्मैसी अध्ययन के लिए अग्रणी संस्थान है।

- सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज शीर्ष दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान है।
- आईआईटी बॉम्बे अग्रणी नवाचार संस्थान है, इसके बाद आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली का स्थान है।
- आईआईटी रुड़की वास्तुकला और योजना में शीर्ष संस्थान बना हुआ है।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु सातवें वर्ष भी शीर्ष लॉ स्कूल है।

➤ अन्य तथ्य -

- शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जेएनयू को सबसे कम अंक मिले, जबकि आईआईएससी को सबसे अधिक अंक मिले।
- इस रिपोर्ट में शीर्ष संस्थानों में डॉक्टरेट-योग्यता प्राप्त संकाय के संकेन्द्रण पर प्रकाश डाला गया है, जिससे मार्गदर्शन और संकाय की तैयारी प्रभावित हो रही है।
- विभिन्न प्रकार के संस्थानों में पीएचडी धारक संकाय की संख्या में काफी भिन्नता है, फार्मैसी संस्थानों में यह 32.30% से लेकर प्रबंधन संस्थानों में 93.45% तक है।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (Clean Plant Programme)

संदर्भ : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दे दी है, जिसे भारत में बागवानी फसलों की उपज और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।

➤ स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) का अवलोकन

- फरवरी 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।
- इसका उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

➤ वित्तपोषण और आवंटन

- कृषि मंत्रालय ने सीपीपी के लिए 1,765 करोड़ रुपये की मांग की है।
- वित्तपोषण स्रोत: इसके लिए आधी राशि एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) बजट से तथा आधी राशि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण के रूप में प्राप्त की गई है।

➤ सीपीपी के घटक

- स्वच्छ संयंत्र केंद्र (सीपीसी)
 - इसमें रोग निदान और चिकित्सा के लिए नौ सी.पी.सी. की स्थापना की जाएगी।
 - इसमें नर्सरियों के लिए मातृ पौधे तैयार किया जायेगा।
 - साथ ही सभी घरेलू और आयातित रोपण सामग्रियों को क्वारंटाइन (quarantine) किया जायेगा।
- बुनियादी ढांचे में वृद्धि
 - स्वच्छ रोपण सामग्री के सफलता पूर्वक वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों विकसित करना।
 - किसानों को प्रवर्धित पौधे वितरित करना।
- विनियामक और प्रमाणन प्रक्रिया
 - रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री में जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया स्थापित करना।

Face to Face Centres





13 August, 2024

तालिका: स्वच्छ पौध केंद्र (सीपीसी) और उनसे जुड़े आईसीएआर संस्थान

शहर	सीपीसी का उद्देश्य (उत्पादन हेतु)	आईसीएआर से जुड़ा संस्थान
पुणे	अंगूर	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे
बेंगलुरु	आम, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, एवोकैडो	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु
नागपुर	खट्टे फल	केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर
बीकानेर	खट्टे फल	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर
श्रीनगर	शीतोष्ण फल (सेब, बादाम, अखरोट, जामुन)	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), श्रीनगर
शोलापुर	अनार	अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, शोलापुर
पूर्वी भारत	उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधे	आईसीएआर के पूर्वी भारत बागवानी केंद्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड
मुक्तेश्वर	आम, अमरूद, लीची	केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, मुक्तेश्वर
लखनऊ	शीतोष्ण फल	केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ

➤ सी.पी.पी. की आवश्यकता -

- भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है।
- इससे बागवानी फसल क्षेत्र 2013-14 में 24 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 28.63 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा।
- इसी अवधि में उत्पादन 277.4 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 352 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है।
- ताजे फलों का महत्वपूर्ण आयातक और निर्यातक:
 - निर्यात : 2023-24 में 1.15 बिलियन डॉलर।
 - आयात : 2023-24 में 2.73 बिलियन डॉलर।
- वर्तमान में सेब, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसी विदेशी रोपण सामग्री की मांग बढ़ रही है।

➤ वर्तमान में आयात सामग्री -

- सेब के पौधे : आयात 2018 में 21.44 लाख से बढ़कर 2020 में 49.57 लाख हो गया है।
- एवोकैडो पौधे : आयात 2018 में 1,000 से बढ़कर 2020 में 26,500 हो गया है।
- ब्लूबेरी पौधे : आयात 2018 में 1.55 लाख से बढ़कर 2020 में 4.35 लाख हो गया है।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना -

संदर्भ: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 'मॉडल सौर गांव' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं।

➤ पीएम-सूर्य घर के तहत 'मॉडल सोलर विलेज' योजना: मुफ्त बिजली योजना -

- उद्देश्य : इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव की स्थापना करना तथा गांवों को ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना शामिल है।

- वित्तीय आवंटन: इसमें कुल ₹800 करोड़, जिसमें से प्रत्येक चयनित गांव को ₹1 करोड़ आवंटित किए जाएंगे।

• पात्रता :

- इसमें शामिल होने के लिए राजस्व उत्पादन करने वाले गांव होना चाहिए।
- जनसंख्या : 5,000 से अधिक (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 2,000) होनी चाहिए।

• चयन प्रक्रिया:

- गांवों का मूल्यांकन उनकी वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा संभावित उम्मीदवारों की घोषणा के छह महीने बाद मूल्यांकन किया जाता है।

- पुरस्कार : प्रत्येक जिले में सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले गांव को ₹1 करोड़ का केंद्रीय वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।

- कार्यान्वयन : इसे डीएलसी पर्यवेक्षण के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

- योजना अनुमोदन: भारत सरकार ने 29 फरवरी, 2024 को इसे मंजूरी दे दी है।

• पीएम-सूर्य घर का उद्देश्य:

- सौर छत क्षमता में वृद्धि करना।
- आवासीय घरों को स्वयं बिजली उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना।

- योजना अवधि: यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 तक चलेगी।

➤ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम मुफ्त बिजली योजना) अवलोकन

- प्रारंभ तिथि: 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना 15 फरवरी, 2024 को शुरू की गई थी।

Face to Face Centres





13 August, 2024

- **छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा:** शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।
- **वित्तीय सहायता:** प्रत्यक्ष सब्सिडी और स्थापना लागत के लिए उपलब्ध किरफायती ऋण के कारण लाभार्थियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए):**
 - इसमें 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60% सब्सिडी दी जाएगी।
 - 2-3 किलोवाट (अधिकतम 3 किलोवाट) के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त 40% सब्सिडी दी जाएगी।
 - 1 किलोवाट प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता राशि ₹230,000, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए ₹260,000, तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए ₹278,000 दिया जाएगा।
- **आवेदन प्रक्रिया:** इसमें परिवारों को एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, जो सिस्टम के आकार, लाभ और विक्रेता रेटिंग के बारे में विवरण प्रदान करता है। फिर वे स्थापना के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करेंगे।
- **वित्तपोषण विकल्प:** इसमें 3 किलोवाट तक की स्थापना के लिए बिना किसी जमानत के, लगभग 7% की दर से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हैं।
- **अतिरिक्त सुविधाओं:**
 - **आदर्श सौर गांव:** ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक जिले में विकसित किए जाएंगे।
 - **स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन:** इसमें छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना के स्थानीय प्रचार को प्रोत्साहित करता है।
 - **भुगतान सुरक्षा:** यह अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के लिए भुगतान सुरक्षा का समर्थन करता है।
 - **नवप्रवर्तन निधि:** छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में नवीन परियोजनाओं के लिए समर्पित निधि दी जाएगी।
- **अपेक्षित प्रभाव:** इस योजना से 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने और बिजली की लागत में सालाना लगभग 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
- **अवधि और परिव्यय:** यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 तक 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।
- **पात्रता मापदंड:**
 - परिवार का सदस्य भारतीय नागरिक होना चाहिए।
 - सौर पैनलों के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए।
 - वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
 - पहले कभी सौर पैनलों के लिए सब्सिडी प्राप्त नहीं की हो।
- **डिस्कॉम की भूमिका:**
 - डिस्कॉम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के रूप में नामित किया गया है और वे नेट मीटर की उपलब्धता, निरीक्षण और प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार हैं।
 - उन्हें अतिरिक्त ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, इस घटक के लिए वित्तीय परिव्यय 4,950 करोड़ रुपये होगा।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

हाल ही में, भेल ने यह साझा किया है कि उसने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से 1,600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना हासिल की है।

भेल के बारे में:

- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग और विनिर्माण वाली कंपनी है जो विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन, निर्माण और स्थापित करती है।
- इसकी स्थापना 1956 में सोवियत प्रौद्योगिकी की मदद से की गई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है।
- यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है।
- यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है, जो प्रति वर्ष लगभग 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है।
- कंपनी को देश में भारी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में बनाया गया था।
- BHEL के उत्पादों और सेवाओं में बिजली उत्पादन (थर्मल, हाइड्रो, गैस, परमाणु और सौर पीवी), ट्रांसमिशन (परिवहन, रेलवे, ऊर्जा, जल, तेल और गैस, रक्षा और एयरोस्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में) और व्यापक बिजली संयंत्र सेवाएँ (इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, सर्विसिंग और मूल्यांकन) शामिल हैं।

भेल



Face to Face Centres





13 August, 2024

सीमा सड़क संगठन



सीमा सड़क संगठन (BRO) ने सिक्किम में इंद्राणी पुल का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया है, जो अक्टूबर 2023 में अचानक आई बाढ़ से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद राज्य के उत्तरी क्षेत्र को शेष भारत से फिर से जोड़ता है।

सीमा सड़क संगठन के बारे में:

- सीमा सड़क संगठन (BRO) भारत में रक्षा मंत्रालय के तहत एक कार्यकारी बल है जो सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 1960 में भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए की गई थी।
- यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित 21 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में काम करता है और अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में अपने बुनियादी ढाँचे के संचालन का विस्तार भी करता है।
- इसे सशस्त्र बलों के युद्ध आदेश में भी शामिल किया गया है, जो किसी भी समय उनका समर्थन सुनिश्चित करता है।
- इसका आदर्श वाक्य "श्रमण सर्व साध्यम्" है, जिसका अर्थ है "कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है"।
- नवंबर 2021 में, BRO को लद्दाख में उमलिंग ला में निर्माण के बाद "सबसे अधिक ऊंचाई वाली सड़क" के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला।

कलिंग पुरस्कार



हाल ही में, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र से यूनेस्को कलिंग पुरस्कार को बंद न करने का आग्रह किया।

कलिंग पुरस्कार के बारे में:

- विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा व्यक्तियों, संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) या अन्य संस्थाओं को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिन्होंने विज्ञान या प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है।
- यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है।
- इसकी स्थापना 1951 में भारत में कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष बिजोयानंद पटनायक ने पेरिस में यूनेस्को को 1,000 पाउंड दान करने के बाद की थी।
- यह यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में भारत का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है।
- विज्ञान मंत्रालय 2001 से यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार का समर्थन कर रहा है।
- इस पुरस्कार में 40,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है और विजेता को डीएसटी द्वारा स्थापित कलिंगा चेयर भी मिलती है, जिसमें 5,000 अमेरिकी डॉलर का नकद हिस्सा होता है।
- पुरस्कार समारोह बुडापेस्ट में विश्व विज्ञान दिवस समारोह के दौरान होता है, जहाँ प्राप्तकर्ता यूनेस्को और भारत का अतिथि होता है।

वन इंडिया-वन टिकट



हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन इंडिया-वन टिकट की शुरुआत की गई।

वन इंडिया-वन टिकट के बारे में:

- "वन इंडिया-वन टिकट" पहल भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और क्रिस के बीच सहयोग है।
- इस पहल का उद्देश्य भारतीय रेलवे और आरआरटीएस सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है।
- यह यात्रियों को लचीले भुगतान के साथ आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नमो भारत टिकट बुक करने की अनुमति देगा।
- प्रत्येक टिकट पर इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची (ईआरएस) पर एक अद्वितीय क्यूआर कोड मुद्रित होगा।
- इस पहल में क्यूआर-कोडेड टिकट, 120-दिन की अग्रिम बुकिंग, क्यूआर विवरण के साथ एसएमएस/ईमेल पुष्टि, चार दिन की टिकट वैधता और आईआरसीटीसी वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध बुकिंग शामिल है।

Face to Face Centres





DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

DAILY pre PARE

Current affairs summary for prelims

13 August, 2024

POINTS TO PONDER

- हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सेहरावत किस खेल से जुड़े हैं? – कुश्ती
- हिंद महासागर में हाल ही में नामित तीन पानी के नीचे की संरचनाओं के नाम क्या हैं? – अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु
- द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास 'उदार शक्ति 2024' में किन देशों ने भाग लिया? – भारत और मलेशिया
- हाल ही में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर किसे मिला है? – द्रौपदी मुर्मू
- 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 योजना' को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय सम्बंधित है? – आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com